GENERAL INSURANCE EMPLOYEES' ALL INDIA ASSOCIATION
(Affiliated to Trade Union International)
e-mail address: - gieaia1971@yahoo.com
Sterling Cinema Building, Third floor,
No.65, Murzban Road, Fort, Mumbai –400 001
Working Office: 15-16, Scindia House, KG Marg, New Delhi-110001

President : AMARJEET KAUR **Working President:R.SRINIVASAMURTHY**
General Secretary: TRILOK SINGH **Addl. General Secretary: A.KUMARVELU**
email:trilokpundeer@gmail.com
email: kumargieu222408@gmail.com

21 अक्टूबर, 2022

आपके सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाशन और मीडिया में प्रसारण हेतु

जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन ने अगस्त 2022 से देय वेतन संशोधन को कर्मचारी व कम्पनी के प्रदर्शन से जोड़ने यानि के0पी0आई0 (Key Performance Indicator) पालिसी को एकतरफा व असंवैधानिक ढ़ंग से थोपने और एलआईसीआई के साथ हाल के वेतन समझौते में समानता की कमी के खिलाफ 17.10.2022 को पूरे देश में गेट मीटिंग कीं और 19.10.2022 को देश के सभी कार्यालयों में इस एकतरफा फैसले के खिलाफ भोजनावकाश में विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही सभी कर्मचारियों ने 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक काला फीता बांधकर इन मुद्दों पर अपना विरोध प्रदर्शित किया ।

इस सम्बंध में सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमा कर्मचारियों के पांच वर्षों से अधिक के निरंतर संघर्ष के पश्चात उनके वेतन में 12.05% की वृद्धि दी गई जबकि कर्मचारी बीमा सेक्टर में समानता बनाए रखने के लिए एलआईसीआई के बराबर वृद्धि की मांग कर रहे थे । इसके अतिरिक्त यह भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेसर्स ई एंड वाई , सलाहकार की पूरी रिपोर्ट साझा किए बिना यानि एकतरफा व असंवैधानिक तरीके से अगस्त, 2022 से देय वेतन संशोधन को कंपनी और कर्मचारी के व्यक्तिगत प्रदर्शन (KPI) के साथ जोड़ा गया है ।

जनरल इंश्योरेंस इम्पलाइज आल इंडिया एसोसिएशन (GIEAIA) ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इसके विरोध में 17.10.2022 को देश भर में गेट मीटिंग की तथा 19 अक्टूबर 2022 को भोजनावकाश के समय पूरे देश में सभी केन्द्रों पर KPI के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही 19 अक्टूबर से आज 21 अक्टूबर, 2022 तक, इस एकतरफा निर्णय के खिलाफ सभी कर्मचारी काला फीता पहन कर अपना विरोध प्रदर्शित किया।

यह गंभीर चिंता का विषय है कि आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां जिन्होंने 2012 से 2017 तक के वर्षों के लिए अच्छा मुनाफा और लाभांश दिया और विभिन्न सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, करोना कवच पालिसी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ग्रामीण व फसल बीमा और पीएम एस बी वाई (PMSBY) जहां नाममात्र प्रीमियम रु0 12/- प्रति व्यक्ति पर दो लाख रुपए की आकस्मिक मृत्यु कवर इत्यादि योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया और वो भी जब कोविड काल में सरकारी साधारण बीमा के लगभग 500 कर्मचारियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, इन कम्पनियों के कर्मचारियों को पिछले 62 महीनों के लंबे संघर्ष के बाद भी आशानुरूप वेतन वृद्धि नहीं दी गयी ।

सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों ने वर्ष 2012 से 2017 की अवधि के दौरान 10,000 करोड़ से अधिक का सरकार को लाभांश के रूप में योगदान दिया । सरकार ने आईपीओ के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त किए और लगभग 60,000 करोड़ सरकारी खजाने में जीएसटी के रूप में जमा हुए । इन कंपनियों ने लगभग 20,000 करोड़ का मुनाफा कमाया और सभी सामाजिक योजनाओं के कार्यान्वयन पर 37,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाया । सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियाँ , राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीय हित में समाज और बड़े पैमाने पर लोगों की सेवा के लिए गठित की गई थीं और इन कंपनियों ने सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू किया है । विभिन्न प्रकार की आपदाओं की स्थिति में दावा के रूप में भारी राशि का भुगतान किया है, गरीब वर्ग का उत्थान किया, युवाओं को रोजगार दिया, सरकार को भारी लाभांश दिया और हर सम्भव सामाजिक कार्यों को पूरा किया लेकिन ऐसा लगता है कि आजसमाज के सामाजिक कल्याण को दरकिनार कर दिया गया है और मुनाफाखोरी को ही इस प्रमुख सेवा क्षेत्र का एकमात्र पहलू घोषित कर दिया गया है । इसी कारण वर्ष 2022 से व्यक्ति और कंपनी का प्रदर्शन जो किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केंद्र में प्रचलित नहीं है को वेतन संशोधन के साथ जोड़ना अपरिहार्य हो गया है ।

यह नीति, यदि लागू की जाती है, तो इससे निजीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा और KPI के नाम पर अंततः की सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाले निजीकरण को प्रोत्साहित करेगा । सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज डीएफएस अधिकारी सरकारी साधारण बीमा कंपनियों को निजी कम्पनियों के समान अवसर प्रदान करने जैसे गंभीर व वास्तविक मुद्दे पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के अनैतिक व्यवहार कोनियंत्रित करने में डीएफएस विफल रहा है ।

जनरल इंश्योरेंस इम्पलाइज आल इंडिया एसोसिएशन, बड़े पैमाने पर पॉलिसी धारकों, कर्मचारियों और आम नागरिकों के व्यापक हित में सार्वजनिक क्षेत्र की सभी साधारण बीमा कंपनियों का तत्काल विलय कर एलआईसी के अनुरूप एक एकल मोनोलिथिक निगम का गठन करने का आह्वान करता है ।

जनरल इंश्योरेंस इम्पलाइज आल इंडिया एसोसिएशन ने, KPI आधारित वेतन संशोधन, समान अवसर प्राप्त करने के लिए, वंचितों, किसानों, बीमाधारकों, बेरोजगार युवाओं व आम नागरिकों के व्यापक हित में, आर्थिक स्थिरता और एकल मोनोलिथिक कॉर्पोरेशन की मांग को लेकर संघर्ष का देशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया है ।

(त्रिलोक सिंह)
महासचिव
जनरल इंश्योरेंस इम्पलाइज आल इंडिया एसोसिएशन

(TRILOK SINGH)
GENERAL SECRETARY